

14 दिसंबर, 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स के साथ साक्षात्कार – श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

आपको गवर्नर बने दो वर्ष हो गए हैं। एक नौकरशाह के तौर पर अपनी पिछली भूमिका की तुलना में इस भूमिका में आने वाली चुनौतियों के बारे में आप क्या कहेंगे?

कई चुनौतियाँ रही हैं और एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल है। महामारी सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है, जिससे आर्थिक संकट भी पैदा हुआ है। यह घटना अपने आप में 100 वर्ष में एक बार होती है। गवर्नर के साथ सीधी जवाबदेही का स्तर बहुत अधिक होता है। आरबीआई में, सारा दारोमदार गवर्नर पर ही होता है। जब आप सरकार में होते हैं, तो आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं और जवाबदेही सरकार पर होती है। इसका अर्थ है राजनैतिक। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, आपको पहले दिन से ही एक सबडिवीजन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ कानून और व्यवस्था के मुद्दे होते हैं जिनसे निपटना होता है। लेकिन आरबीआई में यह भूमिका अब तक की सबसे बड़ी है। आप जो भी करते हैं और जो भी नहीं करते हैं, उसका असर अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार पर पड़ता है। आपको सही समय पर सही कदम उठाना होगा।

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक (इसीबी) जैसे केंद्रीय बैंकों ने बाजार को चलनिधि के साथ चालू रखने के लिए रिस्पॉन्स दिया है। आरबीआई ने भी ऐसा ही किया। आप अपनी कार्रवाई को कैसे देखते हैं?

जब हम महामारी में गए, तो देशों में पहले से ही एक साथ मंदी थी। वित्तीय बाजार सूख रहे थे। भारत में, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार रुक रहे थे। हर केंद्रीय बैंक को घरेलू हालात पर प्रतिक्रिया देनी थी। कोई टेम्पलेट नहीं था। फरवरी में, हमने एलटीआरओ (लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन्स) घोषित किया। चीन में वायरस के दूसरे देशों में फैलने की बात हो रही थी। मैंने अपने फरवरी वक्तव्य में यह कहा था कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। पहला था एक सामान्य चलनिधि कार्रवाई। हमें यह भी एहसास हुआ कि कुछ बैंकों के पास रेपो विंडो के ज़रिए चलनिधि के लिए काफी अधिक सरकारी बॉन्ड नहीं थे। इसलिए, हमने सीआरआर में कटौती की। इसके साथ ही, हमने बैंकों को ऋण देने और आरबीआई के पास अधिशेष को जमा न करने के लिए कहा। हम वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर करीब से नज़र रख रहे थे।

आपने चलनिधि को लेकर आरबीआई के दृष्टिकोण को बदल दिया। वित्तीय बाजार खुश हैं, लेकिन अर्थशास्त्री अगले संकट की चेतावनी दे रहे हैं। जोखिम क्या हैं?

जब हम उपायों की घोषणा करते हैं, तो हम हर उपाय के लिए जोखिम का भी आकलन करते हैं। हम हमेशा नुकसान के जोखिम और उसे कम करने के तरीकों का आकलन करते हैं। चलनिधि डालने से अपना उद्देश्य पूरा हो गया है। बॉन्ड बाजार फिर से शुरू हो गए हैं। एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों), एमएफआई (माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) और दूसरों में चलनिधि का प्रवाह फिर से शुरू हो गया है। अब ज़्यादा चलनिधि विदेशी मुद्रा प्रवाह से है। अगर आप इसीबी और एफईडी की लंबे समय तक दर कम रखने और दो वर्ष तक चलनिधि भरपूर रखने की बात पर भरोसा करें, तो आपको अंतर्वाह मिलेगा। उभरते हुए बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत को एक सुरक्षित और मज़बूत बाजार के तौर पर देखते हैं। हमें नुकसान के जोखिम के बारे में पूरी जानकारी है। हम यह भी विश्लेषण करते हैं कि किस तरह के कमी करने के उपाय की ज़रूरत है या उपाय में ही कौन से सुरक्षात्मक बनाने की ज़रूरत है ताकि यह पक्का हो सके कि इससे दूसरी समस्या न हों। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह संकट दुनिया ने 100 वर्षों में सबसे बड़ा देखा है, जीएफसी (वैश्विक वित्तीय संकट) से और

महामंदी से भी बड़ा। फिर भी, अनिश्चितता बनी हुई है, हालांकि वैक्सीन को लेकर अच्छे संकेत हैं। डर है कि लगातार आसान नीति और बढ़ती महंगाई एक मज़बूत संमिश्रण हो सकता है जो अगले संकट का कारण बन सकता है... और आपने वित्तीय बाज़ारों को आगाह किया। जब आप 100 वर्षों के सबसे बुरे संकट का सामना कर रहे होते हैं, तो आपको विकास को फिर से पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था पर महामारी के विपरित प्रभाव को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होता है। हम इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि समय से पहले कदम पीछे खींचना विकास के लिए नुकसानदेह होगा। वहीं, देर से कदम पीछे खींचने के भी अपने नकारात्मक प्रभाव होंगे। हम इस स्थिति के दोनों ही पहलुओं से पूरी तरह अवगत और सचेत हैं। इसलिए, हमें एक संतुलित और सही समय पर निर्णय लेना होगा। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम सही समय पर सही निर्णय लें। समय से पहले और देर से—दोनों ही स्थितियों में कदम पीछे खींचने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम इस नाजुक स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। मुझे विश्वास है कि हम सही संतुलन बनाने में सफल होंगे। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि बाज़ारों के लिए हमारा भावी दिशानिर्देश अभी भी कायम है और हम उसका पूरी तरह पालन करेंगे।

पिछले 18 महीनों से भी कम समय में तीन बैंक संकट का शिकार हुए हैं। और इस बात से कुछ चिंताएं पैदा हो रही हैं।

हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हमें इस बात की जानकारी थी कि कुछ समस्याएं हैं। हमें उम्मीद थी कि वे बाज़ार-आधारित तंत्र के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ, तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि जमाकर्ताओं का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उन दो बैंकों में किया गया हस्तक्षेप मुख्य रूप से उन बैंकों की विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़ा है और इसका बैंकिंग प्रणाली की व्यापक समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। यह बैंकिंग प्रणाली की मज़बूती पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली अभी भी पूरी तरह से मज़बूत है। बैंकों को अपनी सहनशीलता और मज़बूती बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से पूंजी जुटानी चाहिए।

क्या पर्यवेक्षण और निरीक्षण में कोई चूक हुई है?

पिछले दो वर्षों में, हमने बैंकों और एनबीएफसी के अपने पर्यवेक्षण को काफी सख्त किया है। अब हमारे पास शुरुआती चेतावनी संकेत मौजूद हैं। हमारे पास एक आंतरिक मापदंड है। उदाहरण के लिए, इन संकेतों में से एक है—बैंक का 'बिज़नेस मॉडल' और ऋण-वृद्धि की संरचना। यदि कोई खतरे की घंटी बजती है, तो हम मामले की और भी गहराई से जांच करते हैं। महामारी के दौरान, हम और भी अधिक स्पेसिफिक हो गए हैं और हमने वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों की जांच-पड़ताल को और भी अधिक पैना किया है। हम लघु वित्त बैंकों और 'शहरी सहकारी बैंकों' पर भी गहरी नज़र रख रहे हैं। पर्यवेक्षीय विश्लेषण के लिए सुपटेक (सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और हम लगातार अपने विश्लेषणात्मक प्रणाली को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या डीबीएस का लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) को टेकओवर करना दूसरे विदेशी बैंकों के लिए एक संकेत है?

यह भी महसूस किया जा रहा है कि बैंकों को उबारने के तरीके में कोई एकरूपता नहीं है।

चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अलग-अलग बैंकों की समस्याओं से निपटने के लिए कोई एक जैसा तरीका नहीं है। हर बैंक की स्थिति अलग होती है और उससे उसी हिसाब से निपटना होता है। इसलिए, येस बैंक और एलवीबी के मामले अलग-अलग थे। हमने हर बैंक में उस समय की स्थिति के हिसाब से कदम उठाए। यह हर मामले के हिसाब से अलग होना चाहिए, लेकिन इसका मूल उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

आप विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है?

विकास के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन यह हर तरफ एक जैसा नहीं है। हम यह भूल रहे हैं कि हम अभी मंदी के दौर में हैं। इसलिए, एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) ने विकास को सहारा देने के लिए साफ-साफ आगे की दिशा दी है, साथ ही उभरते हुए समष्टि आर्थिक स्थिति पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है।